The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now. we continue with the discussion on the working of the Ministry of Information and Broadcasting.

Shri Satya Prakash Malaviya. Your party has got 24 minutes. Mr. Kamal Morarka is also here. So, you decide how much time you will take.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभाध्यक्ष जी, यह जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है इसके कार्यकरण पर चर्चा के माध्यम से इस सदन को यह मौका मिला है कि इस विभाग की कार्य प्रणाली है उसके ऊपर आंकलन कर सकें और किसी भी देश में जो सरकारी मीडिया है या इस विभाग से संबंधित जो विभाग हैं उनसे इस बात की जानकारी होती है कि किस प्रकार से वे विभाग काम कर रहे हैं। यह जाहिर बात है कि जो सरकारी मीडिया है कम से कम भारत जैसे देश में कि देश के एक कोने में क्या घटित हो रहा है या दूसरे कोने में क्या घटित हो रहा है इसके बारे में उसको सारे देश के लोगों को जानकारी करानी चाहिये। भारत देश गरीब नहीं है हमारे यहां प्रचुर संपदा है। लेकिन यहां के जो लोग हैं उनमें आधे से ज्यादा लोग निरक्षर हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। बुद्धिमान और परिपक्व होते हुये भी क्योंकि उनके पास साधनों का अभाव है इसलिये हमारा देश बहुत से मायनों में पिछड़ा हुआ है। 28 अप्रैल को इसी सदन में सरकारी मीडिया के ऊपर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और जो इस विभाग के मंत्री थे श्री अजीत पंजा उन्होंने अपने वक्तव्य के शुरू में कुछ उद्धरण दिये थे। उन्होंने कहा था कि :

"An informed, educated and enlightened citizenry is the basis of a democratie, country like India. The Government is fully conscious of the role of the official media have to perform in educating and informing the people of the country with a view to galvanising them into a unified force for the socioeconomic and cultural advancement of the country."

यह बात उनकी बिल्कुल सही भी थी। लेकिन आज हमको यह देखना होगा कि वास्तव में यह जो विभाग है और इसके जो उद्देश्य बतलाये गये हैं वह उनको पूरा करने में कहां तक सफल हुआ है। हमारे देश में 82 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इनमें से 7० प्रतिशत लोग जो हैं वे गरीब और निरक्षर हैं। तो इस विभाग का यह भी काम होना चाहिये कि देश से गरीबी कैसे दूर हो, निरक्षरता कैसे दूर हो। हमारे देश में जो सामाजिक कुरीतियां हैं वे कैसे समाप्त हों और इसमें सरकारी प्रचार माध्यमों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मीडिया का काम है जैसा कि खुद ही उसकी वार्षिक रिपोर्ट में बतलाया गया है कि शिक्षा देना, सूचना देना तथा यह जो हमारा जन-मानस है उसको इंटरटेन करना। लेकिन यह काम तभी संभव होगा जब कि सरकारी मीडिया का सदुपयोग हो। इस मीडिया का दुरुपयोग किसी की छवि बिगाड़ने के लिये या किसी की छवि सुधारने के लिये न हो। बहुत सी कमेटियां बनीं। चन्दा कमेटी, फिर दूरदर्शन पर जोशी कमेटी बनी, फिर उसके बाद अभी विश्व बन्धु गुप्ता जी जिक्र कर रहे थे कि दूरदर्शन पर एक नार्मोडिया कमेटी थी। उसके बाद वर्गीस कमेटी थी। अभी चार-पांच दिन पहले लोक सभा में स्टेटस कमेटी की रिपोर्ट भी इस संबंध में प्रस्तुत हुई है। सरकारिया कमीशन जो बिठाया गया था उसने भी इस संबंध में अपने कुछ सुझाव दिये हैं। लेकिन इस पर मैं आऊं उसके पहले 5 जनवरी, 1962 को श्री जवाहर लाल नेहरू का जो भाषण है उसको यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा था कि धनी समूह अथवा धनी राष्ट्र जन संचार के माध्यम से किसी देश और संसार में अपनी विचारधारा का धुंआधार प्रचार कर सकते हैं, जो सही या गलत कैसे भी हो सकता है।

मेरा कहना है कि आज जो मीडिया है सरकारी मीडिया, चाहे वह दूरदर्शन हो, चाहे आकाशवाणी हो उसका दुरुपयोग आज सत्ताधारी पार्टी जो है उसके लिये बहुत नियोजित ढंग से किया जा रहा है और यह भी प्रचार किया जा रहा है कि देश में जो राजनैतिक दलों के लोग हैं उनके विरुद्ध इसके माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसी सदन की कार्यवाही से शुरू करूंगा। 26 अप्रैल या 27 अप्रैल को कर्नाटक के राज्यपाल के विरुद्ध एक प्रस्ताव इस सदन में था। श्री बूटा सिंह जी का उस प्रस्ताव के विरोध में और जो उनका सरकारी प्रस्ताव था उसके पक्ष में, श्री बूटा सिंह जी का भाषण हुआ और उसका उत्तर भी श्री गुरुपाद-स्वामी जी ने दिया। लेकिन शाम को आकाशवाणी और दूरदर्शन में 27 तारीख को एक प्रसारण हुआ। दूरदर्शन में जो प्रसारण हुआ 27 अप्रैल को हिन्दी वाले समाचारों में भी हुआ जो 8.40 से 9.00 बजे तक होता है और अंग्रेजी वाला जो 9.30 से 9.50 तक होता है उसमें भी प्रसारण हुआ। तो दूरदर्शन पर प्रसारित अंग्रेजी समाचार का उद्धरण मैं पढ़ूंगा और आकाशवाणी का हिन्दी वाला उद्धरण पढ़ूंगा।

"Fifty-one Consjress-I Members of Parliament today criticised the Janata Dal leader, Mr. Gurupadaswamy for using what they called derogatory language against the Home Minister Mr. Buta Singh in the Rajya Sabha while moving the motion of censure against the Karnatak Governor In a joint statement in New Delhi, they said, Mr. Buta Singh represents the weaker sections in Parliament and this has caused widespread feelings of pain and anguish among the people. They regretted that some Janata Dal leaders show disrespect towards the weaker sections.

The signatories to the statement include Chowdhury Ram Sewak, Mr. S. S. Ahluwalia, Mr. V. Narayanasamy, Mr. Mirza Irshad Baig, all of whom are Members of this House and Dr. G. S. Rajhans and Mr. D. P. Yadav, both of them are Members of Lok Sabha."

ठीक इसी प्रकार से जो आकाशवाणी है उसका अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में समाचार आया लेकिन हिन्दी में जो समाचार 8.45 मिनट पर आया वह इस प्रकार है :---

"कांग्रेस आई के 51 संसद सदस्यों ने जनता दल के नेता श्री गुरुपदस्वामी की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्हों ने राज्यसभा में कर्नाटक के राज्यपाल के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव रखते हुए गृह मंत्री श्री बूटा सिंह के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली में एक संयुक्त बयान में इन संसद सदस्यों ने कहा कि श्री बूटा सिंह संसद में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह के व्यवहार से लोगों को दुःख हुआ है। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि जनता दल के कुछ नेताओं ने कमजोर वर्गों के प्रति असम्मान दिखाया है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन के दौरान अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर कई तरह की ज्यादतियां हुई। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में चौधरी राम सेवक, श्री एस० एस० अहलुवालिया, श्री नारायण स्वामी, डा० जी० एस० राजहंस, श्री डी० पी० यादव और मीर्जा इर्शादबेग शामिल हैं"।

मेरा निवेदन यह है कि राज्य सभा की जो कार्यवाही है वह इस सदन के समक्ष रखी हुई है। वह एक अधिकृत कार्यवाही है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। हमारे

[Shri Narayanasamy] -

the recovery of these loans started, because the banks have to recover the 'loans to recycle the money for the purpose 'of giving the benefit to the farmers for the ensuing period, unfortunately the political leaders, especially the CPI(M) leaders in rural West Bengal and "the CPI(M) leaders in the Government have launched *a* propaganda that these amounts need not be paid by the farmers. On account of that, the recovery which was 80% and 85% has come down to 33% and 36% respectively. Ultimately what the West Bengal Government will do, when next time the banks will refuse to advance loans,- is to blame the Central Government for this. But the fact of the matter is. that the State Government is not cooperating with the bank officials in this respect. Why I am saying this is because, at the State level Banking Committee meeting which was held and at which the State Government representatives were present, the officers had categorically said to the State Government th?t they should ooperate in recovering their money so that it could be paid to farmers in the next season. But the State Government officials refused to do so. Apart from this, the saddest pa'rt of it is that the State administration is not, cooperating in organizing meeting at block level and panchayat level to recover the money from the farmers. This is very peculiar. The State Government is not coming forward to help the farmers even during the next season. Therefore, Sir, I urge upon the Central Government to issue directions to the State Government to cooperate with the bank officers to recover the money 50 that it would be useful for the farmers in future—*(Interruptions)* I condemn the attitude of the State Government in not cooperating with the bank officers in recovering the money. Thank you, Sir.

(Interruptions)'

SHRI SUNIL BASU BAY (West Bengal): Sir, I join issue with him. •■ *(Interruptions)..*

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal): Does he understand the subject?

(Interruptions)

AN HONOURABLE MEMBER: He is talking all nonsense.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: He does not understand the subject.

[The Vice-Chairman (Shri V. Nara-yanasamy) in the Chair]

SHRI RAOOF VALIULLAH: (Gujarat): Sir, may I congratulate you for taking the Chair?

THE VICE-CHAIRMAN (Shri T. NARAYANASAMY): ■ Thank you.

SHRI M. A. BABY: (Kerala): Or, we have to say something about tfee Special Mention of Mr. Narayanasamy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANSAMY): The Vice-Chairman, Mr. Desai, ruled it out Therefore I can't allow you.

Need to sanction Gas-based Power Stations in Gujarat

SHRI RAOOF VALIULLAH: (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir,- the Government of Gujarat have represented to the Government of India to clear gas-based power projects, in the State of Gujarat. The Chief Minister of Gujarat has, in **a** memorandum on the "Use of gas from Gandhar fields", stated that allocation of gas from' Gandhar fields for various priority sectors is critically required for agricultural, industrial and economic development of Gujarat.

Sir, Gujarat is specially endowed with large reserves of natural gas and these have been definitely identified